



# कर्ट्राइम

दिल्ली व गाजियाबाद से एक साथ प्रकाशित

● नई दिल्ली। रविवार 06 जुलाई-2025

● ग्रंथ: 10 अंक: 197 पेज-08

● RNINo.DELHIN/2015/65364

● मूल्य: ₹3



## बिहार मतदाता सूची संशोधन को लेकर योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में घुनौती दी

पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच चुनाव आयोग की ओर से मतदाता विश्वास गहन पुरीकरण अभियान को लेकर सियासी हलचल मच गई है। अब एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दिवाना खट्टखटाया गया है। वोटर लिस्ट रिवीवर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

एसोसिएशन फरंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से दिवाना याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग का आदेश समाप्त है। इसमें लाखों मतदाता अपने मताधिकार से वर्चित हो सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है।

एसोसिएशन फरंड डेमोक्रेटिक की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुरीकरण (एसआईआर) के लिए रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

दरअसल, चुनाव आयोग के निर्देश में बिहार में वोटर लिस्ट के संचालन के लिए भारत के चुनाव आयोग के संचालन के लिए भारत के चुनाव आयोग की ओर से जारी करें।



साथ में दिए गए दिशा-निर्देशों को भारत के संचालन के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325, 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निवाचक पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन मानने हुए रद करने के लिए रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

इसी को लेकर याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब तक 24.06.2025 के इस आदेश को रद नहीं किया जाता, तब तक यह मनमाने ढंग से और बिना उत्तर प्रक्रिया के लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वर्चित कर सकता है, असली अधिकारी तो दिल्ली में बैठे हैं और वो किसी और ही जगह से संचालित होते हैं।

कमज़ोर कर सकता है। इस तरह संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार कर सकता है। दूसरी तरफ विषय ने इसको लेकर वोटर लिस्ट का नाम दिया है।

**बोटर लिस्ट पर छिड़ी सिवासन :**

बिहार में वोटर लिस्ट के मामले पर पूरी तरह से सिवासन छिड़ रहा है। इस कदम के बाद से विषयी पार्टी इसके खिलाफ नज़र आ रही है। विषय का कहना है कि वोटर लिस्ट जांच के लिए जिस तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं उसके हिसाब से हजारों की संख्या में लोग वोट देने से वर्चित रह सकते हैं। अब इस मामले को लेकर हाल ही में अराजेड़ी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार चुनाव आयोग से मिले हैं।

महागठबंधन के नेताओं को साथ राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में चुनाव आयोग के अधिकारी तो डाकिया है, असली अधिकारी तो दिल्ली में बैठे हैं और वो किसी और ही जगह से संचालित होते हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा कहा? : इसी को लेकर याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब तक 24.06.2025 के इस आदेश को रद नहीं किया जाता, तब तक यह मनमाने ढंग से और बिना उत्तर प्रक्रिया के लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वर्चित कर सकता है, असली अधिकारी तो दिल्ली में बैठे हैं और वो किसी और ही जगह से संचालित होते हैं।

## आज हापुड़ में मुख्यमंत्री करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात लोकसभा सांसद अतुल गर्ग के पास आ गया हापुड़ प्रशासन का बुलावा

गाजियाबाद, करंट क्राइम : मुख्यमंत्री योगी आदिल्यानथ सम्प्र-समय पर अलग अलग जिलों के अधिकारियों के साथ वाताने हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपडेट लेते हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदिल्यानथ अजय यानी आदिल्यानथ अजय यानी आदिल्यानथ अजय यानी आदिल्यानथ के रिवाया को हापुड़ में अधिकारियों के साथ वाताने के जरिए संवाद व्यापारियों के जरिए संवाद स्थापित करते हैं। इस दौरान हापुड़ के सभी अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि वाले इस



सीन में गाजियाबाद का भी नाम आयेगा। व्याकिंग गाजियाबाद का साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए संवाद लोकसभा क्षेत्र आंशिक रूप से हापुड़ में आता है। धौलाना विधानसभा क्षेत्र में और गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में और पिलखुवा का आंशिक क्षेत्र लेंगे तो इस बैठक में अन्होने कहा कि अतुल गर्ग का आपनी व्यापारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद स्थापित करेंगे। इस दौरान हापुड़ के सभी अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि वाले इस

पिलखुवा का आंशिक क्षेत्र गाजियाबाद को आंशिक क्षेत्र करेंगे।

लोकसभा क्षेत्र में आता है। जबकि प्रशासनिक रूप से पिलखुवा, हापुड़ प्रशासन के अधीन आता है। आज जब मुख्यमंत्री की आज होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कानून व्यवस्था और कांवड़ यात्रा के इंतजामों को लेकर अधिकारियों से बात कर सकते हैं। वीकारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों से बात कर सकते हैं। फिलहाल आज जब हापुड़ में सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होंगे तो गाजियाबाद के लोकसभा सांसद अतुल गर्ग भी भी जूड़ रहेंगे। अतुल गर्ग का लोकसभा क्षेत्र में आंशिक रूप से धौलाना और पिलखुवा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद स्थापित करेंगे। इस दौरान हापुड़ के सभी अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि वाले इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद स्थापित करेंगे।

अतुल गर्ग का लोकसभा क्षेत्र में आता है। उनके पास एसएडीएम का पत्र आ चुका है और जब मुख्यमंत्री योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी योगी आदिल्यानथ की ओर से जूड़ी कीसी भी बात को रख सकते हैं।

तेजस्वी





# करंट क्राइम

सिर्फ सच...

03

• नई दिल्ली। रविवार 06 जुलाई - 2025

दिल्ली व गाजियाबाद से एक साथ प्रकाशित

## सरकार ने लगाई पानी की टंकी और कोई उस पानी पर लगा गया ताला

गाजियाबाद, करंट क्राइम। सरकार ने जनता की सुविधा के लिए पानी की मोटर लगाई और पानी की टंकी स्थापित की। दरअसल ये मामला उस खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र का है जहां पेयजल की समस्या रहती है। जहां पानी की सलाई के लिए मुख्यमंत्री से तकलीफ मिले थे और खोड़ा के लिए पानी की बात की थी। इसी पानी को लेकर कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और जब यहां पानी आया तो पानी की टंकी पर कोई ताला ही लगा गया। जनता पानी की कमी से जुँझ होती है और किसी ने पानी की सलाई पर प्राइवेट ताला लगा दिया। ये मामला खोड़ा नगर पालिका परिवर्द्धक क्षेत्र के वार्ड संख्या 8 का है। वहां किसी ने पानी की सलाई पर भोटी चैन बांध कर बड़ा ताला लगा दिया। बताया जाता है कि ये प्राइवेट ताला है और इसकी वजह से पानी की सलाई रुक गई है। अब वे ताला किसने लगाया और क्यों लगाया है वह जांच का विषय है लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि खोड़ा में पानी की टंकी पर प्राइवेट ताला लगा गया है।



### इधर हुई खबर प्रकाशित, उधर खुल गया पार्क का ताला

करंट क्राइम। सरकार की सम्पत्ति पर जनता का अधिकार होता है और एक अंजीब मामला इन्दिराग्राम क्षेत्र का आया था। दैनिक करंट क्राइम ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया। ये मामला इन्दिराग्राम के वार्ड संख्या 8 का था। यहां पर गुलबगाहा नाम का पार्क है इस पार्क पर स्थानीय पार्षद ने ताला डाल दिया था। ताला तीन महीने से लगा हुआ था और पार्षद द्वारा ताला डाले जाने के बाद से स्थानीय लोग इस पार्क में ही नहीं जा पा रहे थे। ताले के पीछे तक ये दिया जा रहे थे कि यहां असमाजिक तर्कों का जागवडा ताला है और पार्क के बाहर अतिक्रमण हो जाता है। अब जन निगम ने नगर निगम के पार्क पर पार्षद के ताले को प्रमुखता से प्रकाशित किया और ये भी बताया कि अगर असमाजिक तर्कों का जागवडा हो रहा है तो इसका समाधान पार्षद पर पार्षद का ताला नहीं है वालिक इसकी सुनान पुलिस की दी जानी चाहिए और पुलिस कार्रवाई की जरूरी। अब पार्क के बाहर अतिक्रमण हो रहा है तो इसके लिए नगर निगम का अतिक्रमण हटायें।



दस्ता है। लोकिन किसी भी पार्षद या अन्य जनप्रतिनिधि को यह अधिकार नहीं है कि वह नगर निगम के पार्क पर ताला डाल दे। दैनिक करंट क्राइम ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया और जन दैनिक करंट क्राइम के तीमों से सिफारिश लाया है। मंडल टीम धोनी की घोषणा होनी है और सभी वाहां वृथत्य अध्यक्ष का भी अपना जनावर है। बूढ़ा अध्यक्ष के घर पर नेम प्लेट ढोल बजाकर लगती है और मंडल प्रधान के लिए केन्द्र के बाजार योगी लोगों ने खबर प्रकाशित हुई तो तीन महीने से खबर प्रकाशित का ताला तीन घंटे के अद्यतन खुल गया। अब लोग पार्क में जा सकते हैं और नगर निगम का पार्क भी पार्षद के ताले से आजाद हो गया है।

कहा ये गया कि जब रविवार को सुबह कार्यक्रमों की आंख खुलेगी तो इंटरट की ओरपांग हो चुकी होगी सभी बता रहे हैं कि किंवदं भी मंडल होल्ड पर नहीं है। सभी मंडलों की सूची आ रही है। 20 मंडलों के पदाधिकारियों की टीम धोनी हो रही है खास बात ये बताइ जाती है कि इस बार मंडल की टीमों में भी समीकरण साधा गया है। मंडल टीम में महिला, ओबीसी, एससी वर्ग को समायोजित किया गया है। इसके अलावा मंडल टीम में पदाधिकारी का मानक मूल कार्यक्रम है। और अब उस पर क्षेत्रीय अध्यक्ष की मुहर लगनी है। सब्र बताते हैं कि शनिवार को टीम धोनी करने वाले सीन में तेजी आ गई। क्षेत्र वाले दफ्तर कार्रवाई पर ज्यादा कार्यक्रम किया गया है। वहां वरिष्ठ कार्यक्रमात्मकों को भी मंडल में स्थान मिलेगा।

### पार्षद बोले लोगों की शिकायत पर लगाया था ताला

करंट क्राइम। वहीं इस पर मामले पर शीर्ष अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने ये ताला स्थानीय अपनी मर्जी से नहीं लगाया विकल्प स्थानीय लोगों ने उनसे शिकायत की। लोग यहां लघु शाक कर रहे थे और पार्क को गंदा कर रहे थे। इससे पार्षद में आने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। गुलब वर्ड का पार्क में जो गेट पर ताला लगा था समिति के लोगों द्वारा लगाया था जिसे आज संस्कार में लेकर खुलवा दिया गया है लोगों का कहना है कि गंदी से बदने के लिए ताला लोगों द्वारा लगाया गया था। जिसे खुलवा दिया गया है।

## ग्रेटर गाजियाबाद के प्रस्तावित गठन को लेकर पूर्व पार्षद हिमांशु लव ने उठाया सवाल कहा ग्रेटर गाजियाबाद विषय पर मुख्यमंत्री दें कृपा ध्यान



**COMING SOON**  
ग्रेटर गाजियाबाद  
जल्द आ रहा है?



गाजियाबाद करंट क्राइम। पूर्व पार्षद हिमांशु लव ने ग्रेटर गाजियाबाद के प्रस्तावित गठन को लेकर सवाल उठाया है। पिछले दिनों मान सरोवर भवन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आये थे और उन्होंने गाजियाबाद नगर के लिए घोषणा की। ग्रेटर गाजियाबाद नगर के लिए घोषणा की। ग्रेटर गाजियाबाद नगर निगम के खोड़ा नगर पालिका, लोनी नगर पालिका और मुरादनगर नगर पालिका का विवर करते हुए।

ग्रेटर गाजियाबाद नगर में वर्तमान में 100 वार्ड हैं जिनमें से लगभग 16 वार्ड ऐसे हैं, जिनके साथ देहात क्षेत्र भी जुड़ता है। अधिकारी ग्रेटर गाजियाबाद नगर निगम भवन कर, बढ़ोत्तरी के झारड़े में जो कि शहरी क्षेत्र से भवन कर, की टंकी पर लगाया गया है।

अधिकारी ग्रेटर गाजियाबाद नगर निगम भवन कर, बढ़ोत्तरी के झारड़े में जो कि शहरी क्षेत्र से भवन कर, की टंकी पर लगाया गया है।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को देखना चाहिए।

ग्रेटर गाजियाबाद का विवर करते हुए, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकल्पों को

## संपादकीय

### फेक न्यूज पर कानून

**दे** शे में इंटरनेट का प्रसार बढ़ रहा है और आर्टिकल इंटरिंगेस तथा डीपोर्क के इस्तमाल में भी तेजी से इजाजत हो रही है। ऐसे में जीजी खबरों यानी फेक न्यूज के कारण सामाजिक व्यवस्था और लोकतात्रिक मूर्चों के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। उनसे निपटने के लिए हमें सावधानीपूर्वक संतुलन कायम करना होगा। अपेक्षाकृत तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिवर्तन में तकनीकी रूप से पिछड़ी सरकारी मशीनों का इस्तेमाल करना निष्प्रश्न तो पर समस्या ऐप्स कराया। ऐसे में यह अवधिक है कि भारत में अधिकारी उत्तर जान वाले नियमितीय कानूनों को लेकर सरकार रहे।

दुर्गम्यता इन दिनों को नॉर्मन्स में यह अहीं है। राज्य सरकार ने एक मस्तिष्क विधेयक तयार किया है जो फैजी खबरों या अन्य दिक्षितहृषि सम्पादी तैयार करने पर सात वर्ष तक का कानून की बात कहता है। यहां समस्या यह है कि फेक यानी हाफ्फी खबरों की परिभाषा तय करने का कानून एक विशेष समिति के हवाले कर दिया गया है जिसकी बात विधेयक में की गई है। इस कानून का इरादा समाज जो सकता है लेकिन यह इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे कानून का अत्यधिक इस्तेमाल भी समस्याएँ पैदा कर सकता है। कॉर्टिक नॉर्मन्स ने इस बात पर सम्मुचित विवाद नहीं किया कि इसका अधिकारी की शक्तियां पर क्या असर होगा।

विधेयक एक रसीदी सम्पाद्य को प्रदर्शित करता है जो किसी एक राज्य भर की नहीं है। देश में सभी रसीदों पर सरकारी अधिकारी अधिकारी बहुत हाद तक अधिकारिकी पर प्रतिवेद्य लागा के कानून में लगे हुए हैं। कैंट्रो सरकार ने कई अवसरों पर सूना प्रौद्योगिकी नियमों को संशोधित किया है ताकि वह रसीदों को अधिक शक्ति संपन्न बना सके और अनलाइन प्लेटफॉर्म पर अकुश लागा सके। गत वर्ष सितंबर में बैंबु उच्च न्यायालय ने उन बलालों के एक पहले को नकार दिया था जिनके जरिये सरकार एक हाफ्फेट वेक शुनिहर लागा सकती थी जिसके तहत भारी इंटरनेट से कोई खबर हटाने का आदेश दिया जा सकता था।

कानून व्यवस्था की प्राथमिक विधेयकी राज्य सरकारों की होती है और उन्होंने भी ऐसे तरीके तलावों की तेजी दिखाई है जो उह अधिकारी की जाजीरी पर अकुश लागा में मदद करें। इस राज्यों ने फेक वेक विधेयक कानून की पांच पूर्वी कानूनों में पहले कुछ राज्यों ने तो इसके भी आगे बढ़कर कानून उठाया है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के तथा विवादित हाफ्फार्नन नकासल के खिलाफ विल प्रस्तावित किया है। इस शब्द का प्रयोग अक्सर वाम धड़े के असल चरमपंथियों के लिए नहीं (युक्तिकाम्यता से इन दिनों यह समस्या समाप्त हो रही है) बल्कि अकादमिक तत्र में सत्ता से असहमत लोगों के लिए किया जा रहा है। ऐसे कानूनों से अलग भी राज्यों के अधिकारियों और स्थानीय सरकार के अधिकारियों में कानून-व्यवस्था के नाम पर इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने को लेकर लागू बढ़ा जा रहा है। कई बार तो एक दिन निचले स्तर पर के अधिकारी भी ऐसे आदेश देते हैं।

विकास के क्षेत्र में बाधाओं की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी दिवकर अपरस्थाही और नियाकारी क्षमता है। खासतौर पर राज्य सरकार पर। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार कम होती इस क्षमता को उन प्रणालियों की ओर मोड़ा जा रहा है जो देश में अधिकारीकी जाजीरी को प्रतिवेद्यता या अधिकारित होती है। यह संविधानिक अनिवार्यता को तो उल्लंघन है, जी देश की आवादी की विकास आवाजाओं के साथ भी धोखा है। यह बात घट्टतर्पण है कि देश की सरकारें इस मामले में पीछे हटे हैं और आपने रुख को नए सिरे से परेखा। अनुबंध प्रत्यन्त में शिथित हो जाए है और जांचों में देखी होती है। क्या फैजी खबरों या हाफ्फतरनाक अधिकारिकी से निपटने के नाम पर नए अपराधिक मामलों और जांचों को जोड़ना आवश्यक और उचित है? कैंट्रो सरकार का कानूनी ढाई में अपराधीकरण करने का इच्छा सही होता है। इस सिद्धांत को केवल कानून तक लागू न रखकर सामान्य सासन में भी लागू किया जाना चाहिए।

## 2026 की पहली तिमाही में थमी रहेगी महांगाई



नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में महांगाई दर भारतीय उत्पादन के अनुरूप रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुरूप रहने की उम्मीद है। यह स्थिति एक अनुरूप सांख्यिकीय आधार और अवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संधारन के लिए उत्पादन के अनुरूप रहने की संभावना है।

रिपोर्ट में बताया गया कि जून में उपयोगी कामों की सूचनाकंक (सीपीआई) 2.6% पर स्थिर रहने की संभावना है। इससे यह सकेत मिलता है कि निकट भविष्य में आरबीआई के पास विकासी-सूचीयों तथा उपयोगी उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कानूनी विधान दिखाए जाएं।

टिप्पणी के अनुसार, वैश्विक कामों की कीमतों में उत्पादन के अनुरूप रहने की उम्मीद है। यह स्थिति एक अनुरूप सांख्यिकीय आधार और अवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संधारन के लिए उत्पादन के अनुरूप रहने की संभावना है। इस राज्य के अनुरूप रहने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2026 के लिए

सीपीआई 3.7 रहने का अनुमान :

केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए खुदरा मुद्रास्पदीति (सीपीआई) का अनुमान 3.7 प्रतिशत लगाया है। पहली तिमाही के लिए 2.9%, दूसरी तिमाही में 3.4%, तीसरी तिमाही में 3.9% और चौथी तिमाही में 4.4% रहने की संभावना जतायी गई है।

बीओबी आवश्यक वस्तु सुचकांक में गिरावट : जून 2025 में बीओबी आवश्यक वस्तु सूचकांक (बीओबी ईसीआई) में वार्षिक अधिकारी पर 1.8% की गिरावट दर्ज की गई, जो मई 2025 के 0.6% से अधिक है। यह लगातार तीसरी महीना है, जब उसका वस्तु सुचकांक क्षेत्र में बना हुआ है।

दालों की कीमतों में तेज सुधार, बहेतर उत्पादन के अनुकूल अपूर्ति रिजर्व बैंक के कानूनों के अनुरूप रहने की उम्मीद है। यह स्थिति एक अनुरूप सांख्यिकीय आधार और अवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संधारन के लिए उत्पादन के अनुरूप रहने की संभावना है।

लगातार गिरावट के लिए उत्पादन के अनुरूप रहने की उम्मीद है। इससे विकासी-सूचीयों की कीमतों में संधारन के लिए उत्पादन के अनुरूप रहने की संभावना है।

दालों की कीमतों में तेज सुधार, बहेतर उत्पादन के अनुकूल अपूर्ति रिजर्व बैंक के कानूनों के अनुरूप रहने की उम्मीद है। यह स्थिति एक अनुरूप सांख्यिकीय आधार और अवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संधारन के लिए उत्पादन के अनुरूप रहने की संभावना है।

दालों की कीमतों में तेज सुधार, बहेतर उत्पादन के अनुकूल अपूर्ति रिजर्व बैंक के कानूनों के अनुरूप रहने की उम्मीद है। यह स्थिति एक अनुरूप सांख्यिकीय आधार और अवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संधारन के लिए उत्पादन के अनुरूप रहने की संभावना है।

दालों की कीमतों में तेज सुधार, बहेतर उत्पादन के अनुकूल अपूर्ति रिजर्व बैंक के कानूनों के अनुरूप रहने की उम्मीद है। यह स्थिति एक अनुरूप सांख्यिकीय आधार और अवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संधारन के लिए उत्पादन के अनुरूप रहने की संभावना है।

दालों की कीमतों में तेज सुधार, बहेतर उत्पादन के अनुकूल अपूर्ति रिजर्व बैंक के कानूनों के अनुरूप रहने की उम्मीद है। यह स्थिति एक अनुरूप सांख्यिकीय आधार और अवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संधारन के लिए उत्पादन के अनुरूप रहने की संभावना है।

दालों की कीमतों में तेज सुधार, बहेतर उत्पादन के अनुकूल अपूर्ति रिजर्व बैंक के कानूनों के अनुरूप रहने की उम्मीद है। यह स्थिति एक अनुरूप सांख्यिकीय आधार और अवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संधारन के लिए उत्पादन के अनुरूप रहने की संभावना है।

दालों की कीमतों में तेज सुधार, बहेतर उत्पादन के अनुकूल अपूर्ति रिजर्व बैंक के कानूनों के अनुरूप रहने की उम्मीद है। यह स्थिति एक अनुरूप सांख्यिकीय आधार और अवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संधारन के लिए उत्पादन के अनुरूप रहने की संभावना है।

दालों की कीमतों में तेज सुधार, बहेतर उत्पादन के अनुकूल अपूर्ति रिजर्व बैंक के कानूनों के अनुरूप रहने की उम्मीद है। यह स्थिति एक अनुरूप सांख्यिकीय आधार और अवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संधारन के लिए उत्पादन के अनुरूप रहने की संभावना है।

दालों की कीमतों में तेज सुधार, बहेतर उत्पादन के अनुकूल अपूर्ति रिजर्व बैंक के कानूनों के अनुरूप रहने की उम्मीद है। यह स्थिति एक अनुरूप सांख्यिकीय आधार और अवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संधारन के लिए उत्पादन के अनुरूप रहने की संभावना है।

दालों की कीमतों में तेज सुधार, बहेतर उत्पादन के अनुकूल अपूर्ति रिजर्व बैंक के कानूनों के अनुरूप रहने की उम्मीद है। यह स्थिति एक अनुरूप सांख्यिकीय आधार और अवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संधारन के लिए उत्पादन के अनुरूप रहने की संभावना है।

दालों की कीमतों में तेज सुधार, बहेतर उत्पादन के अनुकूल अपूर्ति रिजर्व बैंक के कानूनों के अनुरूप रहने की उम्मीद है। यह स्थिति एक अनुरूप सांख्यिकीय आधार और अवश्यक वस्तुओं की कीमतों में संधारन के लिए उत्पादन के अनुरूप रहने की संभावना है।







